RJPP, Vol. XXIII, No.I, Oct.24-Mar.25, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411
Impact Factor 8.858

ग्रामीण भारत में सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन

हरीश राम
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग
हर्ष विद्या मंदिर (पी.जी.) कॉलेज,
रायसी, हरिद्वार उत्तराखण्ड
ईमेलः harishhitaishi1@gmail.com

सारांश

समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव चलते रहती है। विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है, जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो क्योंकि परिवर्तन ही समाज नियम है। इतिहासकार हेनरी सननर मैन ने अपनी पुस्तक "Ancient Law" में लिखा है कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ता है। वर्तमान युग में ग्रामीण भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय गाँव की तरफ एक सामाजिक दृष्टिकोण डाला जाए तो परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ग्रामीण समाज व्यवस्था में समूह, समुदाय, समितियों, संस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज भारतीय ग्रामीण जन–जीवन में परिवर्तन क्रांति के रूप में देखने को मिलती है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, जजमानी प्रथा, नातेदारी व्यवस्था, ग्राम पंचायत, धार्मिक संस्थाओं, परंपराओं और स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हो गए हैं।

भारतीय गाँव में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन आधुनिक युग में कृषि के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से यंत्रीकरण हो चुका है। भारतीय गाँव में शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बाद जन–जन अंधविश्वास और भाग्यवाद में विश्वास नहीं करते। ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। आज गाँव में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, पर्दा–प्रथा जैसी कुप्रथाओं का धीरे–धीरे अंत हो गया है। भारतीय गाँव में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 18.11.2024
Approved: 22.03.2025

हरीश राम

ग्रामीण भारत में सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन

RJPP Oct.24-Mar.25, Vol. XXIII, No. I, Article No. 14 Pg. 111-119

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2025-vol-xxiii-no1

और राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन् भारतीय गाँव में आज आत्मनिर्भरता भी देखने को मिलती है।

समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भारतीय गाँव के विभिन्न पहलुओं में आज निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं –सामाजिक कुरीतियों में नवीन चेतना, धार्मिक कर्मकांडों के महत्व में कमी, धर्मनिरपेक्षता, परिवार, विवाह, नातेदारी सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, संपत्ति के अधिकारों में परिवर्तन, परंपरागत व्यवसाय के महत्व में कमी, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, धार्मिक प्रवृत्तियों में स्थिरता, स्त्री की स्थिति में परिवर्तन, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा, बाल विवाह में कमी, विवाह पिक्चर का प्रचलन इत्यादि।

मुख्य शब्द

सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मानदंड, सोशल मीडिया, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सामाजिक संस्था, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण।

प्रस्तावना

समाज व संस्कृति में परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है, भारतीय गाँव में सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति में आधुनिकता व परंपराओं में नवीनीकरण का समन्वय दिखाई देता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, प्राचीन काल से ही भारतीय गाँव के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वर्तमान युग में बढ़ते आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण से ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में ही नहीं वरन संपूर्ण सामाजिक संरचना, व्यवस्था, संगठन, मूल्य, आदर्श, सामाजिक मानदंड सभी में परिवर्तन हुआ है। समाज की प्रथम इकाई परिवार से लेकर राष्ट्र तक निरंतर परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना में जाति, धर्म, वर्ण–व्यवस्था, आश्रम–व्यवस्था, संस्कार, विवाह का स्वरूप, नातेदारी, जजमानी व्यवस्था इत्यादि सभी इकाइयों में परिवर्तन हुए हैं।

शोध अध्ययन का उद्देश्यः

- वर्तमान ग्रामीण भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- ग्रामीण जनजीवन पर सोशल मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावों का अध्ययन करना।
- ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, सामुदायिक प्रथाओं के परिवर्तन में वैश्विक संस्कृति की भूमिका का अध्ययन।

षोध अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है, जिसमें विभिन्न शोध पुस्तकों, शोध पत्र पत्रिकाओं, दस्तावेज तथा विभिन्न लेखको, ऑनलाइन सरकारी वेबसाइटों का प्रयोग किया गया है, जिसमें वर्णनात्मक और विवरणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन

समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो क्योंकि परिवर्तन ही समाज का नियम है। ब्रिटिश इतिहासकार हेनरी सननर मैन ने अपनी पुस्तक Ancient Law (1861) में बताया कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ता है।

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार– सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।

जिटलिन के अनुसार– सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन का संबंध उन प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा समाज और संस्कृति में बदलाव आता है।

गिडेन्स के अनुसार– सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था में परिवर्तन है।

जॉनसन के अनुसार– मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन से है।

ऑगस्त काम्टे के अनुसार– मानव की बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है।

भारत में ग्रामीण समाज

भारतीय समाज को दो भागों में वर्गीकृत किया गया हैः– ग्रामीण समाज और नगरीय समाज। ग्रामीण समाज, वह समाज जो प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट रहता है। ग्रामीण समाज में सामाजिक संबंधों की अंतःक्रिया घनिष्ठ होती है। ग्रामीण समाज भी दो भागों में विभाजित है, जनजाति समाज और कृषक समाज। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं –

- कृषि पर निर्भरता
- कम जनसंख्या घनत्व
- पारंपरिक जीवनशैली
- मजबूत सामाजिक संबंध
- सामुदायिक भावना
- भूमि स्वामित्व
- शिक्षा और जागरूकता का अभाव
- आर्थिक असमानता
- गरीबी
- प्राकृतिक संसाधनों के साथ घनिष्ठ संबंध

ग्रामीण भारत में सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन

सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तनः– प्राचीन भारतीय गाँव कभी दार्शनिक विचारों पर निर्भर थे। जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति माना जाता था, जिसमें पुरुषार्थः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एवं धार्मिक कर्मकांडों का अत्यधिक महत्व था। वर्तमान समय में दार्शनिक मूल्यों का स्वरूप भौतिकवादी संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो गया है।

पारिवारिक संरचना में परिवर्तनः– परिवार ग्रामीण समाज का एक ऐसा गृहस्थ समूह है, जिसमें तीन पीढ़ी या उसे अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। शहरीकरण, औद्योगीकरण और नगरीकरण के कारण पारिवारिक संरचना अर्थात पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण भारत में वर्तमान समय में प्रचलन बढ़ा है।

जाति व्यवस्था में परिवर्तनः– ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार जाति नामक संस्था है, जो कि प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार रही है।

प्रो० एम० देसाई का कथन है कि भारत में जाति व्यवस्था ही अधिकांश एक व्यक्ति के लिए उसकी प्रस्थिति, कार्यों, अवसरों और प्रतिबंधों के रूप का निर्धारण करती है। ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था के नियमों और प्रतिबंधों में शिथिलता आई है। वर्तमान में जाति का स्वरूप वर्गों ने ले लिया है।

प्रभु जाति अवधारणा में परिवर्तनः– सन् 1959 में प्रो० श्रीनिवासन ने मैसूर के 'रामपुर गांव' के अध्ययन के दौरान प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया। प्रभु जाति का प्रयोग ग्रामीण भारत में स्वामी, भू–स्वामी, काश्तकार, मालिक, साहूकार के लिए किया जाता था जिनकी गाँव में एक अलग प्रतिष्ठा होती थी, लेकिन आज ग्रामीण समाज में प्रभु जाति की संरचना में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया है।

धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तनः– भारत एक धर्म प्रधान, सहिष्णुतावादी देश है विश्व बंधुत्व में अटूट आस्था रखता है।

एडवर्ड टायलर ने कहा है–"धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है"। धर्म समाज में नैतिक मूल्य, आस्था ,सेवा भाव, मूल्यों और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रामीण भारत में धर्म के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। धर्मनिरपेक्षता की जगह आज धर्मनिरपेक्षीकरण का उपयोग हो रहा है अर्थात धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है।

सामाजिक कुरीतियों के प्रति नवीन चेतनाः– ग्रामीण समाज में अंधविश्वास, भाग्यवाद और विभिन्न कुरीतियों– सती प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह इत्यादि का अत्यधिक बोलबाला था, लेकिन ग्रामीण समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव ने इन कुरीतियों में परिवर्तन ला दिया।

मानवतावादी एवं समानतावादी मूल्यों को प्रोत्साहनः– वर्तमान ग्रामीण समाज आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन देते हैं। जिसके कारण भारतीय ग्रामीण समाज में जाति, वर्ग, धर्म, प्रजाति, आयु, लिंग के आधार पर भेदभाव निश्चित रूप से कम हुए हैं।

संपत्ति के अधिकारों में परिवर्तनः– ग्रामीण समाज में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पिता की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होगा, लेकिन 1937 हिंदू स्त्रियों के संपत्ति पर अधिकार अधिनियम ने स्त्रियों को भी संपत्ति पर अधिकार दिए। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता कानून जिसमें स्त्रियों को संपत्ति पर पूरा अधिकार है।

परंपरागत व्यवसाय के महत्व में कमीः– ग्रामीण समाज की प्रमुख आधारशिला के रूप में परंपरागत व्यवसाय का प्रचलन था। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा शिक्षा के समान अवसरों ने सभी लोगों को व्यावसायिक स्वतंत्रता प्रदान की है, जिसमें परंपरागत व्यवसाय की तुलना में नवीन व्यवसाय जो आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा के परिचायक भी हैं।

ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तनः– ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति, धर्म, पंचायत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। संयुक्त परिवार एकांगी परिवार में, विवाह धार्मिक संस्कारों की बजाय एक समझौता रह गया है।

स्त्रियों की प्रस्थिति में परिवर्तनः– ग्रामीण समाज में स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में स्त्रियों को शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार प्रदत हैं। जिसके कारण आज ग्रामीण समाज में महिलाएँ विकास में एक मजबूत आधार स्तंभ है।

कृषि अर्थव्यवस्था तथा उत्पादन प्रणाली में बदलावः– भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है कृषि जीविका का और आय का मुख्य साधन है। सामान्यतः ग्रामीण समाज में उत्पादन

और उपभोग के मध्य संतुलन बना रहता है, अपने सीमित साधनों में ग्रामीण अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। अब ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज की आर्थिक–सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाना जिससे कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था सुधार हो सके और ग्रामीणों के रहन–सहन का स्तर अच्छा और प्रगतिशील बन सके।

भू–स्वामित्व एवं श्रम व्यवस्था में परिवर्तनः– भू–स्वामित्व जिसमें भू–स्वामी, जमींदार, काश्तकार, मालगुजारी, जोतदार के आधार पर भूमि और श्रमिक व्यवस्था बटी हुई थीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे–धीरे भू–स्वामित्व और श्रमिक संरचना में अर्थात श्रमिकों के अधिकार कर्तव्य और दायित्व में परिवर्तन हुए। परंपरागत भू–स्वामित्व व्यवस्था में बदलाव देखने को मिले।

ग्रामीण सामाजिक संगठन में परिवर्तनः– रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण भारत सामाजिक संरचना को समझने के लिए सामाजिक संगठन, परिवार, नातेदारी, धर्म, जाति, शिक्षा, सत्ता एवं अर्थव्यवस्था आदि आधारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रत्येक गाँव अपनी स्थानीय आवश्यकताओं जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि की पूर्ति ग्रामीण स्तर अपने ही समूह और समुदायों में करता है लेकिन आज ग्रामीण सामाजिक संगठनों में बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है।

सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक संगठन में परिवर्तनः– पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से ग्रामीण समाज में सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण समाज पर सामाजिक प्रतिबंध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्योग्यताएँ समाप्त हो रही है। उद्योग–धन्धों के विकास के कारण आर्थिक आधार पर संगठन बने जिससे जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त हुआ और जाति का स्वरूप वर्गों ने लिया। मशीनीकरण के कारण छुआछूत खानपान के प्रतिबंध शिथिल हुए। यातायात के साधनों का विकास हुआ जिससे जनसंपर्क में वृद्धि हुई, संस्कृतियों का आदान–प्रदान हुआ। भारत में तीव्र औद्योगीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिले। वर्तमान में ग्रामीण समाज आर्थिक विकास के परिणाम स्वरुप सामाजिक वर्गों का निर्माण हो रहा है।

ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाएँः

जनतंत्रीकरण (Democratization)– ग्रामीण समाज में परिवर्तन का प्रमुख कारक जनतंत्रीकरण है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार जो जन–जन को प्राप्त है। जिसमें समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे के आदर्श निहित हैं, जो ग्रामीण परंपरागत समाज पर प्रभावी रही है।

आधुनिकीकरण (Modernization) – आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ। जिसने भारतीय समाज की सभी पक्षों को अत्यधिक प्रभावित किया। आधुनिकता एक वह प्रक्रिया है जिसमें परंपरागत समाज समूहवाद, रूढ़िवाद, नियतिवाद, भाग्यवाद से मुक्ति प्राप्त करता है। आधुनिकीकरण मूल्यों और दृष्टिकोण के निश्चित दिशा में रूपांतरण की एक मानसिक प्रक्रिया का सार है।

पश्चिमीकरण (Westernization) – पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भी ग्रामीण समाज और संस्कृति को प्रभावित किया है। आजादी के बाद यह प्रभाव अधिक बढ़ा है। पश्चिमी देशों की संस्कृति, खानपान, रहन–सहन, वेशभूषा, विचारों के आदान–प्रदान का प्रभाव ग्रामीण समाज पर स्पष्टतः देखने को मिलता है।

नगरीकरण (Urbanization) – भारत में पिछले अनेक दशकों में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रक्रिया ग्राम वासियों की नगर की ओर बढ़ती हुई दर और नगरीय तौर–तरीकों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की व्यापकता को प्रकट करती है।

औद्योगिकरण (Industrialization) – औद्योगिकरण केवल उत्पादन की तकनीकी और ढंग के बदलने का नाम नहीं है, अपितु यह आदर्श और मूल्यों को बदलने की एक प्रक्रिया भी है। भारत में आज तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है, जिससे ग्रामीण सामाजिक संरचना के आर्थिक ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

लौकिकीकरण (Secularization)– लौकिकीकरण की प्रक्रिया धीरे–धीरे धर्म को केवल धर्म के क्षेत्र तक सीमित करते जा रही है। खान–पान व वेशभूषा, रहन–सहन आदि उसके प्रभाव क्षेत्र से अलग हो रहे हैं। ग्रामीण समाज में रूढ़िवादियों का स्थान आज विज्ञान और तर्क ने ले लिया है।

संस्कृतिकरण (Sanskritization) – संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की आंतरिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से समाज में निम्न जातियाँ अपने से उच्च जातियां के संस्कार व कर्मकांडों को अपनाकर सामाज में उच्च स्थान का दावा कर रही हैं।

राजनीतिकरण (Politicization) – राजनीतिकरण के माध्यम से ग्रामीण समाज में राजनीतिक घटनाओं, शक्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

ग्रामीण जनजीवन पर सोशल मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव

सोशल मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है, जो ग्रामीण समाज में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास जैसे पहलुओं को प्रभावित करती है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी का ग्रामीण समाज पर एक तरफ सकारात्मक वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ग्रामीण जनजीवन पर सोशल मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव निम्नलिखित है।

सकारात्मक प्रभाव :–

- **शिक्षा और तकनीक तक पहुँचः** डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन शिक्षा, ई–लर्निंग संसाधन और विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
- **स्वास्थ्य सेवा में सुधारः** टेलीहेल्थ और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
- **आर्थिक विकासः** ई–कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और आय के नए अवसर पैदा करती है।
- **सामाजिक विकासः** सोशल मीडिया और डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण समाज विकास में अहम भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया ग्रामीण लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
- **कृषि व्यवस्था में सुधारः** डिजिटल तकनीकें किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, मौसम की जानकारी और बाजार की जानकारी तक पहुँच प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है।

- **स्थानीय प्रशासन में सुधारः** ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने, सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक जुड़ाव में सुधार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

नकारात्मक प्रभावः– सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग ग्रामीण समाज में बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पर अधिक निर्भरता के कारण ग्रामीण जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं।

- **सामाजिक अलगाव या दूरीः** सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग लोगों को वास्तविक दुनिया से दूर कर सकता है और सामाजिक अलगाव पैदा कर सकता है।
- **साइबर अपराध को बढ़ावाः** सोशल मीडिया के प्रति उपयोग से ग्रामीण समाज में वर्तमान में साइबर अपराध जैसे डाटा चोरी, हैकिंग, फिशिंग इत्यादि बैंकिंग से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं।
- **युवा मानसिकता पर कुप्रभावः** सोशल मीडिया का सबसे अधिक प्रभाव युवा समाज पर पड़ा है। वर्तमान में युवा विभिन्न वेबसाइटों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है।
- **गलत सूचनाओं का प्रसारः** सोशल मीडिया पर गलत सूचना और भ्रामक जानकारी का प्रसार तेजी से होता है, जो सामाजिक तनाव और भ्रम पैदा कर सकता है।
- **पारंपरिक मूल्य और संस्कृति पर प्रभावः** सोशल मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति पर नकारात्मक हो सकता है।
- **डिजिटल डिवाइडः** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी के कारण डिजिटल डिवाइड बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, सामुदायिक प्रथाओं के परिवर्तन में वैश्विक संस्कृति की भूमिका

वैश्विक संस्कृति ने ग्रामीण जनजीवन, लोक संस्कृति, सामुदायिक प्रथाओं, परंपराओं, रीति–रिवाजों में बदलाव लाए हैं। जिससे ग्रामीण समाज में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास में तेजी से कमी आ रही है। वैश्विक संस्कृति के कारण संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल मीडिया, डिजिटल तकनीक सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं।

- **संचार और प्रौद्योगिकी का प्रभावः–** संचार और प्रौद्योगिकी संसाधनों ने ग्रामीण समाज को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ा है जिससे ग्रामीण समाज की जीवन शैली में जागरूकता बढ़ी है। नई तकनीक ने ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धतियों और रोजगार के क्षेत्र में भी बदलाव लाए हैं।
- **शिक्षा का प्रभावः–** वैश्विक संस्कृति के प्रभाव से ग्रामीण समाज में शिक्षा का अत्यधिक प्रचार–प्रसार हुआ है। वैश्विक संस्कृति के आदान–प्रदान से ग्रामीण समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जन जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा ने ग्रामीण समाज को नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान किया है।
- **आर्थिक परिवर्तनः–** वैश्वीकरण और शहरीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया है जिसमें कृषि की जगह गैर कृषि गतिविधियों में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग–धंधे, व्यापार, रोजगार के विभिन्न अवसर पैदा हुए हैं, जिससे ग्रामीण समाज में लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है।

- **लोक संस्कृति और सामुदायिक प्रथाओं पर प्रभावः–** वैश्विक संस्कृति के आदान–प्रदान से ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति, जनजीवन, सामुदायिक प्रथाओं, परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है।

- वैश्विक संस्कृति ने सामुदायिक प्रथाओं को भी प्रभावित किया है, जिससे कुछ लोग अपनी पारंपरिक सामाजिक संरचना और मूल्यों को भूल गए हैं।
- वैश्विक संस्कृति ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए सांस्कृतिक रुझानों और जीवनशैली को भी जन्म दिया है, जिससे लोगों के जीवन में विविधता आई है।
- वैश्विक संस्कृति ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मूल्यों और रीति–रिवाजों को चुनौती दी है, जिससे कुछ लोग अपनी संस्कृति को खोने का डर महसूस कर रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु सुझाव

आज भी भारत के 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वह पूर्ण रूप से कृषि और इसे जुड़े कानून पर निर्भर है। भारत के अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रो की महत्वपूर्ण भूमिका है, अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारों को खेती के साथ इससे जुड़े हुए उद्योगों के विकास पर फोकस करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण और मछली पालन के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। ग्रामीण भारत की समृद्धि कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, इसकी वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी अब भी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग–धंधे, फैक्ट्रियां बहुत कम है। सरकार के प्रयासों के बावजूद आज भी ज्यादातर खेती पुराने तौर–तरीको से हो रही है, ऐसे में खेती से किसानों की आय दिन–प्रतिदिन घट रही है। 2002–03 में परिवार की कुल आय में खेती का योगदान 40 प्रतिशत था और 2018–19 में यह घटकर 36 प्रतिशत रह गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना होगा। तकनीकी आधारित खेती को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण और खेती से जुड़े दूसरे उद्यम लगा कर ही ग्रामीणों की आय को बढ़ाया जा सकता है। पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, तकनीकी आधारित कृषि को अपनाकर ग्रामीण युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार दिया जा सकता है। इसके लिए युवाओं को बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन और अनुदान की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वरोजगार के लिए युवाओं को आसानी से लोन मिल सके। इसमें निहित जोखिम भी सरकार को उठाना होगा क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के बिना ऐसा हो पाना संभव नहीं है।

उपसंहार

ग्रामीण भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शहरीकरण, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा और संचार जैसे कारकों के कारण पारंपरिक सामाजिक मूल्यों, रीति–रिवाज और संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आते हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं जो प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। ग्रामीण समाज में विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो न केवल ग्रामीण समाज को

रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था उपलब्ध कराये बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा, सड़क, संचार, पेयजल, बिजली व स्वच्छता के स्तर पर भी ग्रामीण समाज को समृद्ध करते हुए उन्हें समानता के अवसर उपलब्ध कराये। ग्रामीण समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जिससे समाज और संस्कृति के बीच संबंधों और अंत क्रियाओं में परिवर्तन आते हैं और साथ–साथ सामाजिक मूल्यों में भी बदलाव आते हैं। यह बदलाव शहरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, पंथनिरपेक्षीकरण, पश्चिमीकरण जैसे कारकों की वजह से ही होते हैं।

संदर्भ

1. शर्मा, विहारी सवालिया, (2003), ग्रामीण भारत के सर्वोन्मुखी विकासः एक परिदृश्य, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. शर्मा, राजेंद्र कुमार, (1997), रूरल सोशियोलॉजी, अटलांटिक प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. कर्ण, एम० एन०, (2003), सोशल चेंज इन इंडिया, एनसीआरटी प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. यादव, सुबह सिंह, (1991), ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर राजस्थान।
5. श्रीनिवास एम० एन०, (1987), द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर ऐसेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।
6. अग्रवाल, बीना, (1994), अ फिल्ड ऑफ़ वन्स आन : जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
7. चौहान, बी० आर०, 'भारत में ग्रामीण समाज' (1988), ए० सी० ब्रदर्स, उदयपुर।
8. दुबे, एस० सी०, 'इंडिया चेंजिंग विलेज' (1958), लंदन, रूटज एंड किंगन पाल।
9. गुप्ता एम० शर्मा, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पी 155.164।
10. https://www.egyankosh.ac.in/handle/123456789/103736?mode=full
11. https://www.villagesquare.in/four-hurdles-to-social-change-in-rural-india/
12. https://www.sarthaks.com/3102355/